SHRI K. MOHANAN; I just Want to know from the hon. Minister whether the Border Roads Organisation is under the Ministry of Defence or not. I want to know whether they are under the Defence Department or the C.P.W.D. Sir. we are raising the question regarding the problems of the employees of this Border Roads Organisation because when we approach the Defence Department, they are saying no, it is With the CPWD and When we approach the CPWD, they are saying that it is under the Defence Department. So, we would like to know from the Minister whether this Border Roads Organisation is under the Defence Department or under the CPWD.

SHRI SANTOSH .MOHAN DEV: li is under the Defence Department. But, 1 think certain labourers are casual labourers.. .

SHRI K. MOHANAN; Not casual labourers but permanent labourers.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Permanent labourers are also dot actually the Defence personnel. They have got certain terms of employment and it in guided by those. It will be wrong to say that it is In no way connected with the CPWD.

SHRI K. MOHANAN; Sir. they are nowhere; they are neither with the Defence Department nor with the CPWD. That is why I have asked this categorical question,

MR. CHAIRMAN: Question No. 227.

"227. *[The questioner (Shri Oaya (hand Bliiiyan) was absent. For answer,* vide *col.* 35 *infra].*

MR. CHAIRMAN : Question No. 228

Additional outlay for irrigation schemes of Madhya Pradesh

*22S. SHRI AJIT P. K. JOGI :f
SHRI PR1THIBI MAJHI;

Will the Minister of PLANNING be pleased to state;

(a i what idditional outlay, if any, was approved bj the P! inning Commission for various irrigation schemes in Madhya Pradesh, under the drought relief programme:

(bj what amount therefrom has so far been released to the State; and

(c) whether the State Government have requested for any further additional outlay in this regard, if so, what is Planning Commission's response thereto?

i'T'he question was actually asked on the floor of the Housu by Shri Ajit P. K. Joel.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI B1REN SINGH ENG-TI) : (a) Planning Commission has approved additional outlay of Rs. 27 crores for 1987-88 to enable the Govt, of Madhya Pradesh to expedite the completion of specified ongoing irrigation schemes/components of schema as part of the drought relief programmes.

(b) Additional outlay mentioned above is to b_e funded to the extent of 50 per cent from ceiling,- i jiltire sanctioned for employm aeration programmes under 1987 drought and the balance 50 per cent through additional assistance which is also to be made available as part of drought relief programme. The arijttrt^^-a^sistaiir;'-; would be forthconaiag'only after atfeast 80 per cent of the Plan provision foi these pro jects has been utilised. The State Govt, has not so far raised any claim for the release of thi_s assistance,

(e) No Sir. The State Government has not requested for any further additional outlay in this regard.

श्री अजीत जोगी : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल 27 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान रखा गया है जबकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां लगभग हर साल सूखा पड़ता है और हर साल सिचाई के काम प्रारंभ होते हैं । आज स्थिति यह है कि वहां ढाई हजार सिचाई के अपूर्ण कार्य हैं जिनको पूरा करने के लिये लगभग 3 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी । इसको देखते हुए जो 27 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन दिने

को बात कही गयी है यह बहुत ही कम है। इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मध्य प्रदेश के ढाई हजार अपूर्ण सिंचाई के कार्यों को देखते हुए तथा इसके लिये 3 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता को देखते हुए क्या इस आवंटन को बढ़ाने का विचार किया जायेगा ।

. HNISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPL'-J ENTATION; : SHRI P. SH1V SHANK iR): Sir what is relevant for the pu.'t oses of additional outlay i_s that there is ilready an outlay in the 7th Plan for irrig tion purposes. Schemes have been identified in drought prone areas, irriga-ion fa< lilies have to be provided. So whej-evei it has been thought that additional o itlay should be provided so that an impe us is given for those schemes, ii Is only n such cases that an amount of Rs. 23 > crores in 14 States all over the country has been earmarked taking into consider tion that if a little fillip is given to thotf schemes the irrigation facilities will b< more and production of food-grains *t* ould increase. That way, from po f I of view of rhe need-based approa({ as th_e hon 3te{nbei- is trying are quite, a large num bet' of •chemes and theses "SfifeafiSg— s|ajl bin he Slate sector. That is why we have si ratified that where we "thought that an idditional help to the State could be prc\ Jed so that the schemes get complex *i* and the foodgrains production goes up it is only in siicn cases that this decision has been taken, which my colleagtK has also clarified.

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि यह जो अतिरिक्त आवंटन विभिन्न राज्यों को दिया गया है, वह किस आधार पर दिया गया है, क्योंकि जो दूसरे प्रांतों को अतिरिक्त मदद दी गई है, वह मध्य प्रदेश जैसे देश के सब से बड़े प्रांत की तुलना में बहुत अधिक है, विशेषकर राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश को हम से बहुत अधिक आवंटन दिया गया है ।

तो मैं जानना चाहूंगा कि यह आवंटन किस आधार पर दिया गया है और क्या मध्य प्रदेश के आवंटन को बढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी ?

दूसरा, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह जो 27 करोड़ देने की बात की गई है, वह भी दो हिस्सों में देने के विषय में उत्तर में उल्लेख किया गया है । उसमें से अभी तक कितनी राशि हमें दी जा चुकी है और 27 करोड़ पूरा हमको कब तक दिया जाएगा ।

श्री पी० शिवशंकर : हमने उत्तर में ही निवेदन किया है कि जहां तक एडीशनल आऊटले का संबंध है, वह किस तरह से दी जायेगी यह मेरे साथी ने अभी पढ़ कर सुना दिया है । यह उन स्कीम्स से संबंधित है जो स्कीम्स पूरी हो सकती हैं थोड़ी बहुत यदि सहायता की जायेगी । इसका क्राइटीरिया सिर्फ यह है । अब यह कहना कि दूसरे प्रदेशों को ज्यादा दिया गया है, मैं यह नहीं समझता कि यह सही है और यह इस वास्ते कि मेरे सामने दूसरी स्टेट्स के फिगर्ज हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे मध्य प्रदेश को ही काफी कुछ ज्यादा दिया गया है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको ज्यादा आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता की बात अलग है और स्कीम्स को सामने रखते हुए जिनका अध्ययन प्लानिंग कमीशन ने किया है और हम यह समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से थोड़ी बहुत सहायता देने से इन कार्यों की पूर्ति होगी और फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसी ही स्कीम्स की हद तक हमने इसको नियमित किया है । यह कहना गलत है कि दूसरे प्रदेशों को ज्यादा दिया गया है ।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, 27 करोड़ में से अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है । इस वास्ते कि 80 प्रतिशत का जो पहले उन्होंने प्रावधान किया है अपने प्लान में, उसको खर्च करने की जरूरत है । उसके बाद ही वह पूछ सकते है । तभी तो यह पैसा दिया जाएगा लेकिन होगा यह कि यदि यह पैसा दिया

जायेगा, तो वह अपने प्लान में से कुछ भी खर्च नहीं करेंगे और फिर यह भी पैसा खर्च हो जायेगा । इसी वास्ते यह एडीशनल आऊटले का प्रावधान एक खास स्थिति में किया गया है ।

श्री सत्यपाल मलिक : मान्यवर, मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग सभी प्रदेशों में जो स्टेट्रोल्ड इरिगेशन है, जैसे ट्यूबवैल्ज वगैरह, उस पर आऊटले बहुत घट रहा है । मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में ट्यूबवैल्ज और सरकारी क्षेत्र के ट्यूबवैल्ज की क्या स्थिति है ?

श्री पी० शिवशंकर : सर, यह प्रश्न जो है वह एडीशनल आऊटले से संबंधित है । आप इसमें ट्यूबवैल्स का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसके लिये वह दूसरा प्रश्न दें ।

Pak I resident's Statement on Siachin

229. DR. BAPU KALDATE;
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state;

(a) whether Gorerflmenfg attention bas 'been drawn to the statement made by the Pakistan President as reported in th? 'Hindustan Times'/flated the 14th January, 1988 to the effec/ that Siachen was a r[JI]'t of Pakistan and/ that the Pakistani troops were engaged in a Holy war which was contrary to his earlier statement in September, 1986 t_0 the *effect* thai it a no man's'land; and

(b) if so, what is the reaction of Gov ernment with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANTOSH MOHAN DEV) : (a) Gov-ernment have seen the press report in question.

*The question was actually asked on the .floor of the House by Dr. Bapu Kakiate.

(b) While our troops arc prepared to meet any threat to this area which is an integral part of India, Government are in favour of a peaceful resolution of ail bilateral issues.

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह हिन्दुस्तान का हिस्सा है, लेकिन बारबार आप देखते हैं कि जैसे कोई जिया बारबार अपना रवैया बदलते हैं और लगातार कई सालों से वहां पर लड़ाई चलती रही है ।

तो मेरा पहला सवाल तो यह होगा कि इस इलाके में जो गये कई सालों से लड़ाई चलती आई है, इसमें कितने लोग मारे गये और विषम हवा के कारण घायल हो गये इसमें आज तक कितने लोग मारे गये और कितने घायल हो गये ? उनकी संख्या क्या है, यही मेरा पहला सवाल होगा ?

रक्षा मंत्री श्री के० सी० पन्त : सभापति जी, लोग मारे भी गये और घायल भी हुए और वह सब लड़ाई के कारण नहीं, बल्कि वहां ऐसी परिस्थितियां हैं और इस तरह से वहां जितनी ठंडक है, उसमें फ्रास्टबाईट वगैरह भी हो जाती है, एवलांचेस हैं और उन सब की वजह से काफी लोग वहां हताहत हुए । मैं इनकी संख्या यहां बताना ठीक नहीं समझता हूं लेकिन अगर माननीय सदस्य को दिलचस्पी हो, तो मैं उनको अलग से वह संख्या दे सकता हूं ।

डा० बापू कालदाते : महोदय, मैं एक तरफ और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट का हमने जिक्र किया सवाल लिया में उसमें जिया ने यह कहा है कि thai Siachen was a part of Pakistan and the Pakistani troops ware engaged in a Jehad.

वह कर रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि लड़ाई भी जारी रहेगी और दूसरी तरफ पीसफुल नेगोसिएशन भी करते हैं हमको बताइये कि लड़ाई समाप्त होगी और यह पीसफुल नेगोसिएशन से कोई सैटलमेंट होगा, ऐसी आशा लगती है ? अगर लगती है तो इस दिशा में क्या कदम उठाने